संचार मंत्रालय
MINISTRY OF
COMMUNICATIONS

सत्यमेव जयते

संचार मंत्री का संदेश — दूरसंचार विभाग

नमस्कार!

इस महीने की शुरुआत में, देश भर में हममें से कई लोग अपने फोन पर आए इमरजेंसी अलर्ट टेस्ट मैसेज से चौंक गए थे। हालांकि ऐसे अलर्ट हमें कुछ पल के लिए चौंका सकते हैं, लेकिन वे बेहद जरूरी बात सामने लाते हैं। वह बात यह है कि संकट की घड़ी में, सही वक्त पर प्रदान की गई जानकारी लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसी जिम्मेदारी की भावना के साथ हमने स्वदेशी 'सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम' (सीबीएस) लॉन्च किया, जिसे सी-डॉट ने एनडीएमए और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सिस्टम की जरूरत शायद ही कभी पड़े, लेकिन जब भी देश के किसी भी हिस्से में कोई आपदा आती है, तो अब भारत के पास अपने नागरिकों तक तेजी से पहुंचने और उन्हें अलर्ट करने के लिए एक मज़बूत, स्वदेशी और भरोसेमंद तंत्र होगा।

मजबूत और नागरिक-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने की यही भावना पूरे दूरसंचार क्षेत्र में हमारे काम को दिशा देती रहती है। पिछले एक महीने में, दूरसंचार विभाग ने कनेक्टिविटी को मजबूत करने, स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने, डिजिटल समावेशन का विस्तार करने और वैश्विक डिजिटल समुदाय के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 'प्रौद्योगिकी विकास और निवेश प्रोत्साहन' (टीडीआईपी) योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी करना था। यह संशोधित ढांचा भारतीय नवप्रवर्तकों का सहायता, स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और वैश्विक दूरसंचार मानकीकरण प्रक्रियाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में भारतीय संस्थानों और उद्योगों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा प्रयास स्पष्ट है: भारत को न केवल भविष्य की प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए, बल्कि उन्हें आकार देने में भी मदद करनी चाहिए।

देश के हर कोने तक डिजिटल पहुंच का विस्तार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस महीने, 'डिजिटल भारत निधि' (डीबीएन) ने राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत राज्य में संशोधित 'भारतनेट कार्यक्रम' को लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार, एपीबीआईएल, बीएसएनएल और एपीएसएफएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूत करने और बेहतर डिजिटल पहुंच और सेवाओं के माध्यम से नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद करेगी।

इस महीने मुझे दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और बीएसएनएल की नेतृत्व टीम के साथ बीएसएनएल के वार्षिक परिणामों और भविष्य के कार्य योजनाओं की समीक्षा करने का अवसर भी मिला। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार संस्थानों को मजबूत करना और उन्हें तेजी से बदलते डिजिटल भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करना हमारी महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है।

भारत दूरसंचार और डिजिटल सहयोग पर वैश्विक चर्चाओं में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जिनेवा में आईटीयू परिषद 2026 की बैठक में भाग लिया और भविष्य के वैश्विक दूरसंचार ढांचे और नीतिगत चर्चाओं को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को दोहराया। इस कार्यक्रम के दौरान मुझे चर्चा में शामिल होने का मौका मिला, खासकर ऐसे समय में जब भारत डब्ल्यूटीएसए और अपनी व्यापक वैश्विक दूरसंचार साझेदारी के बाद निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत, दूरसंचार विभाग ने आईसीटीएस में सहयोग के लिए ब्रिक्स कार्य समूह की दूसरी बैठक का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन चर्चाओं में ब्रिक्स देशों के बीच भविष्य के नेटवर्क, नवाचार इकोसिस्टम, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता झलकती है।

जैसे-जैसे भारत वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, हमारा ध्यान एक ऐसा दूरसंचार इकोसिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है जो सुरक्षित, समावेशी, अभिनव और पूरी तरह नागरिक-केंद्रित हो। हमारी प्रत्येक पहल, चाहे वह कनेक्टिविटी, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वदेशी प्रौद्योगिकी या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र से जुड़ी हो, का मुख्य लक्ष्य लोगों को सशक्त बनाना और भारत को आने वाले अवसरों के लिए पूरी तरह तैयार करना है।

जय हिंद
आपका,
ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
संचार मंत्री, भारत सरकार